



Research Paper

नई शिक्षा नीति 2020 की व्यवसायिक शिक्षा विकसित भारत की आधारशिला

विनोद कुमार कश्यप

पीएचडी (शोध छात्र)
मार्गदर्शक डॉ उषा बवशी
शिक्षा शास्त्र
कलिंगा यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में अपनायी गई नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो छात्र-छात्राओं को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, उससे छात्र-छात्राओं के साथ-साथ परियार, समाज तथा देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचने की आधारशिला रखी जाएगी। व्यवसायिक शिक्षा से राष्ट्रीय के प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक एक ऐसी सुटुड व्यवस्था बन जाएगी, जिससे हमारे राष्ट्र को विकासशील राष्ट्र से एक विकसित राष्ट्र बना देगी।

प्रस्तावना

आज हमारा राष्ट्रीय एक ऐसे दो राहे पर खड़ा है, जहां पर उसे एक ऐसी नई सोच, नई पहल, नई शिक्षा व्यवस्था, नया प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता है। अगर हमारे राष्ट्र को विश्व के प्रत्येक राष्ट्रों के साथ कदम से कदम मिला कर चलना है, तो उसे अपने मूलभूत आधारशिला में परिवर्तन लाना होगा। जिससे वह अपनी आवश्यकता तथा भविष्य की संभावनाओं को पूरा कर सके।

हमारे राष्ट्र की नई सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। इसी शिक्षा नीति में सर्वाधिक व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। अभी तक पुरानी शिक्षा नीति में जो व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, उसे सिर्फ छात्र-छात्राओं को अंक प्राप्त करने वाली होती थी, परंतु नई शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायिक शिक्षा में शिक्षा के प्राथमिक स्तर से ही अनिवार्य शिक्षण प्रशिक्षण प्रत्येक छात्र-छात्राओं को प्रदान करना कर दिया गया है।

विश्व के अन्य राष्ट्रों के लोगों की सोच किसी व्यवसाय को चुन कर अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। जिससे वे तो लाभ कमाते हैं, साथ ही साथ उनके राष्ट्र का भी विकास होता है। इसलिए वह राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र है। परंतु हमारे राष्ट्र में 90% व्यक्तियों की सोच एक नौकरी की रहती है, कि वे सोचते हैं कि नौकरी मिलने पर वह एक अच्छा जीवन जी लेंगे। इसी कारण वह कभी आगे नहीं बढ़ते तथा इसी कारण से हमारा राष्ट्र भी एक विकासशील राष्ट्र बनकर रह गया है।

इसी सोच को बदलने के लिए भारत सरकार एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया, जिससे भारतवासियों की सोच में बदलाव हो इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत व्यवसायिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया। जिससे भारत के प्रत्येक छात्र-छात्राओं के अंदर नौकरी के चाहत के स्थान पर स्वरोजगार या व्यवसाय चुना जा सके।

नई शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायिक शिक्षा

भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति में जो सबसे ज्यादा ध्यान लगाया है तथा सबसे अधिक परिवर्तन किया है, वह व्यवसायिक शिक्षा है। जो नई शिक्षा नीति से पहले व्यवसायिक शिक्षा चली आ रही वह एकमात्र दिखावे की शिक्षा तथा अनुपयोगी शिक्षा थी। उस व्यवसायिक शिक्षा का वास्तविक जीवन से कोई भी लेना-देना नहीं होता था। वह सिर्फ छात्र-छात्राओं को अधिक अंक प्राप्त करने की होती थी। व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत ना तो छात्र-छात्राओं को उचित व्यवसायिक शिक्षा दी जाती थी ना ही उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। जिससे छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण प्राप्त करके वास्तविक जीवन में कोई समानता नहीं रहती थी।

नई शिक्षा नीति 2020 के व्यवसायिक शिक्षा में इन्हीं कमियों को दूर करना, भविष्य की चुनौतियों का सामना करना, विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के साथ-साथ कदम मिला कर चलना, मांग व पूर्ति का संतुलन करना, बेरोजगारी, असमानता, गरीबी आदि को दूर करने के लिए व्यवसायिक शिक्षा में मूलचूल परिवर्तन किया गया, जो एक भारत को विकसित राष्ट्र बनने में आधारशिला बनेगी।

भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहां की जनसंख्या की सौच सरकारी नौकरी की होती है। यहां पर बालकों के अभिभावक शुरुआत से ही उन्हें सरकारी नौकरी के लिए तैयार करते हैं, तथा उसी प्रकार की उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शुरुआत से ही बालकों के विचारों में एक सरकारी नौकरी की चाहत होती है। वह किसी भी प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा शिक्षण से दूर रहते हैं। उनके मन तथा विचारों में अपने अंदर किसी प्रकार का हुनर तथा कौशल को विकसित करने का नहीं होता है। हमारा देश एक ऐसा देश है, जो किसी कौशल या हुनर के बिना आगे बढ़ रहा है। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति-2020 में व्यवसायिक शिक्षा को अधिक से अधिक केंद्र बिंदु मानकर नीतियों को निर्धारण किया है तथा इन नीतियों को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में 19 से 24 वर्ष की आयु के केवल 5% भारतीयों ने व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त की है। यदि हम दुनिया के दूसरे विकसित देशों की तुलना करेंगे तो आपको यह जानकारी आश्चर्य होगा कि डेनमार्क जैसे देश की 50% आबादी को व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त है, वहीं अमेरिका में 52%, जर्मनी में 75% लोगों ने व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त की है। दक्षिण कोरिया में तो 96% आबादी को व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त है। इन संख्या को देखकर लगता है कि हमारे देश में व्यवसायिक शिक्षा को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह पहली बार नहीं है कि जब हम व्यवसायिक शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। बल्कि हर शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। परन्तु अभी तक हमारा ध्यान 11वीं और 12वीं कक्षा के बालकों पर और विशेष रूप से 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ देने वाले छात्रों पर व्यवसायिक शिक्षा का प्रभावी रूप से संचालन न होने का है। एक और महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि हमारे व्यवसायिक छात्रों के भविष्य के लिए कोई रास्ता ही नहीं था क्योंकि जिन छात्रों ने व्यवसायिक शिक्षा का विकल्प चुना वह सामान्य उच्च शिक्षा में नहीं जा सकते, साथ ही व्यवसायिक शिक्षा को हमेशा शिक्षा की मुख्य धारा की तुलना में कम आंका जाना भी प्रमुख कारण है।

व्यवसायिक शिक्षा के उद्देश्य – नई शिक्षा नीति-2020

- व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित सामाजिक भ्रांतियां को दूर करना**

हमारे समाज में व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित बहुत सारी सामाजिक भ्रांतियां होती हैं, क्योंकि पहले की शिक्षा व्यवस्था में व्यवसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा से अलग रखा जाता था। बालकों के अभिभावक को यह समझ नहीं होती थी, कि व्यवसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा से क्यों अलग रखा गया है, उनको लगता था कि अगर हमारा बालक व्यवसायिक शिक्षा में चला जाएगा तो वह सिर्फ किसी एक ही जीवन यापन का मार्ग चुन सकेगा तथा अगर वह सामान्य शिक्षा ग्रहण करता है, तो बालक के लिए अन्य जीवन यापन के मार्ग खुले रहेंगे।

- बालकों को विभिन्न व्यवसाय के महत्व से परिचित कराना**

नई शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न व्यवसाय के महत्व से भी परिचित कराना है। बालकों को उन्हें समझना है कि आने वाला समय विश्व में इतना प्रतिस्पर्धा होने वाला है कि अगर आप अपने आप को एक कौशल तथा हुनर युक्त नहीं होंगे, तो आप दुनिया से तथा समाज से आप बहुत पीछे हो जाएंगे। अगर विश्व में सभी देशों के लोगों के साथ-साथ आपको आगे बढ़ाना है, तो आपको कोई व्यवसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

- समाज, शिक्षण संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्य धारा से एकत्रित करना**

नई शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को समाज तथा शिक्षण संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से मुख्य धारा की शिक्षा को एकत्रित करना भी है। पहले व्यवसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से कम आंका जाता था तथा यह भी माना जाता था कि व्यवसायिक शिक्षा उन बालकों के लिए है, जो मुख्य धारा की शिक्षा के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पाते हैं। परंतु नई शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा को मुख्य शिक्षा के साथ ही जोड़ दिया जाएगा।

- उच्चतर प्राथमिक स्तर से ही बालकों को सामान्य शिक्षा के साथ—साथ व्यवसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करना

नई शिक्षा नीति में बालकों के कक्षा 6 से ही व्यवसायिक शिक्षा का अनुभव प्राप्त कराया जाएगा। कक्षा 6 से ही उन्हें किसी न किसी को व्यवसाय कौशल से परिचित कराया जाएगा तथा उन्हें सामान्य शिक्षा के साथ—साथ व्यवसायिक शिक्षा भी प्राप्त कराई जाएगी।

- यह सुनिश्चित करना की बालकों को कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशल सीखे

नई शिक्षा नीति 2020 में का सबसे प्रमुख लक्ष्य भारतवर्ष के प्रत्येक बालक—बालिकाओं को कम से कम एक व्यवसायिक कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है। जिसकी शुरुआत उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों से की जाएगी। वहां पर प्रत्येक बालक—बालिकाओं को व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित आरंभिक व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी। जिससे यह होगा की बालक के प्राथमिक स्तर पर ही उसकी सोच में व्यवसायिक शिक्षा का असर पड़ जाए।

- व्यवसायिक शिक्षा को चरणों में तरीके से अगले दशक में लागू करना

नई शिक्षा नीति के अनुसार भारतवर्ष में अगले दशकों में व्यवसायिक शिक्षा को एक चरणबद्ध तरीके से सभी प्रकार के स्कूलों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू किया जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा में मुख्य कार्य क्षेत्र का चुनाव कौशल अंतर विश्लेषण और स्थानीय अवसरों के आधार पर किया जाएगा। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस पहल की देखरेख की जाएगी कि स्थानीय उद्योगों के सहयोग से व्यवसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों और व्यवसायिक मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय समिति नेशनल कमेटी का इंटीग्रेशन आफ वोकेशनल एजुकेशन (एनसीआईवीई) का गठन किया जाएगा।

- व्यवसायिक शिक्षा में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना

हमारा राष्ट्र एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। कृषि जगत को पुनर्जीवित करने के लिए हमें एक कुशलता पूर्ण व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इसलिए नई शिक्षा नीति में कृषि शिक्षा को अधिक ध्यान दिया गया है। यद्यपि हमारे देश में कृषि विश्वविद्यालय का प्रतिशत 9 है, परंतु कृषि और संबंधित विज्ञान विषयों में नामांकन उच्च शिक्षा में कुल एक प्रतिशत से भी कम है। कुशल स्नातक तथा तकनीशियनों, नवीन अनुसंधान और तकनीकी तथा कार्य से संबंधित हुए जुड़े बाजार आधारित विस्तार के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि तथा उससे संबंधित विषयों की क्षमता और गुणवत्ता दोनों को अधिक से अधिक परिवर्तन किया जाए, जिससे जो छात्र एवं छात्राएं कृषि से संबंधित व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकें, वह अपने स्वरोजगार तथा व्यवसाय चुनने में आसानी प्राप्त हो सके।

2025 तक व्यवसायिक शिक्षा के लक्ष्य — नई शिक्षा नीति 2020

- विद्यालय और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना

व्यवसायिक शिक्षा को हमारे देश में पुनः शुरू कर उसे सामाजिक कारकों से जोड़ने की आवश्यकता है। देश में व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिले इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिसमें कहा गया है कि 2025 तक स्कूल एवं उच्च शिक्षा के माध्यम से 50% विद्यार्थियों तक व्यवसायिक शिक्षा को पहुंचाना है।

इसके सभी माध्यमिक विद्यालय आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक और स्थानीय उद्योगों आदि से संपर्क तथा सहयोग करेंगे। सभी प्रकार के स्कूलों में हब और स्पोक मॉडल में कौशल प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी।

- भारत के जनसंख्या रूपी संसाधन का पूर्ण लाभ प्राप्त करना

भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यहां के लोगों जीवन यापन करने की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को सरकारी नौकरी पर रखना बहुत ही कठिन कार्य है, इसलिए वर्तमान भारत सरकार ने स्वरोजगार, व्यवसाय, आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा को सर्वाधिक ठोस कदम उठाए हैं।

भारत सरकार ने बहुत सोच समझकर एक ऐसी नई शिक्षा नीति का निर्माण किया है, जिससे कि भारत की विशाल रूपी जनसंख्या का उचित संसाधन हेतु पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। भारत सरकार ने प्रारंभिक स्तर से ही व्यवसायिक शिक्षा पर सर्वाधिक जोर दिया है। सरकार का मानना है कि अगर प्रत्येक बालक व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण कर लेता है, तो उसके अंदर कौशल उत्पन्न हो जाएगा, जिससे वह अपने आप को आत्मनिर्भर तथा जीवन यापन के लिए बना सकता है, साथ ही साथ हमारे समाज, देश तथा विश्व में अपने कौशल के करण वह आगे बढ़ सकता है।

- **माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक विषयों में व्यवसायिक शिक्षा को सम्मिलित करना**

नई शिक्षा नीति में पहले स्तर की शुरुआत कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए पूर्व व्यवसायिक पाठ्यक्रम के साथ की जाएगी। शिक्षण वर्ष के दौरान छात्रों के लिए महत्वपूर्ण व्यवसायिक कौशल जैसे शिल्प, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, धातु सेल, बागवानी, मिट्टी के बर्तन जैसे कई गतिविधियां शिक्षकों द्वारा आयोजित की जाएगी। इन गतिविधियों के अलावा कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 10 दिनों का इंटर्नशिप के माध्यम से अनौपचारिक व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को स्थानीय टेक्नीशियन, कलाकार, शिल्पकार जैसे कुशल व्यक्ति के साथ कार्य करना और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना ताकि छात्रों को यह समझने में मदद मिलेगी कि काम की दुनिया में अलग-अलग व्यवसाय क्या हैं।

- **माध्यमिक विद्यालयों का आई0आई0टी0, पॉलिटेक्निक और स्थानीय उद्योगों के साथ जुड़ाव**

सहभागिता यानी कोऑपरेशन अभी तक व्यवसायिक शिक्षा को हमेशा संस्थान या स्कूल से स्वतंत्र रूप से संचालित की जाती थी, लेकिन अब यह नीति स्थानीय संस्थाओं जैसे कि आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक के साथ सहभागिता करने पर विशेष बल देती है। इसके अंतर्गत व्यापार उद्योग, अस्पताल, कृषि आदि जैसे कई संस्थाओं के साथ व्यवसायिक शिक्षा को जोड़ कर आगे बढ़ाने की योजना है।

इस सहभागिता का उद्देश्य यह है कि व्यवसायिक विषय चुनने वाले छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन एवं उद्योगों के भ्रमण के नए अवसर मिल सकेंगे। इस प्रकार का सहयोग व्यवसायिक शिक्षा के प्रभावी संचालन में अहम भूमिका निभाएगा।

- **उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्वयं या एन0जी0ओ0 और उद्योगों के साथ साझेदारी द्वारा व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना**

नई शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्वयं या किसी एन0जी0ओ0 के माध्यम से विद्यार्थियों को उद्योगों के साथ साझेदारी द्वारा व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि भविष्य में बालक को किताबी ज्ञान तथा व्यवहारिक ज्ञान में कोई अंतर ना रहे। बालक जब किसी उद्योग या कारखाने में भ्रमण करने या इंटर्नशिप करने जाएगा, तो उसे वास्तविक कार्य का भी अनुभव होगा। जिससे वह अपने अनुभव के आधार पर सही तरीके से अपना कार्य कर सकेगा।

- **उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विभिन्न कौशलों में सीमित अवधि के लिए सर्टिफिकेट कोर्स करने की अनुमति देना**

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विभिन्न कौशलों में सीमित अवधि के लिए सर्टिफिकेट कोर्स करने की अनुमति दी जाएगी। इसी क्रम में और साथ ही व्यवसायिक शिक्षा को 50% पहुंचने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी लेकिन भारत में ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, जो अपनी पढ़ाई मुक्त शैक्षिक व्यवस्था के माध्यम से पूर्ण करते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान मुक्त शिक्षा प्रदान करने वाली एकमात्र संस्थान आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्तमान में राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान के लगभग 5% छात्र जो कि लगभग 27 लाख हैं आज व्यवसायिक पाठ्यक्रम की ओर उन्मुख हैं इसलिए राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान यानी कि एन0आई0ओ0एस0 द्वारा व्यवसायिक शिक्षा में मुक्त एवं दूररथ शिक्षा पाठ्यक्रम की शुरुआत करने की योजना बनाई जा रही है।

- **भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यवसाय ज्ञान लोक विधा से जुड़े विषयों को व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए**

भारत एक सांस्कृतिक विरासतों का देश है। हमारे यहां कई पारंपरिक कलाएं भी हैं जिसे भारत में विकसित किया गया है। लोक विधा के व्यवसायिक पाठ्यक्रम में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। यह सब करने के लिए एन0एस0क्यू0एफ0 के तहत माध्यमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक व्यवसायिक पाठ्यक्रम की उच्च विभिन्न डिग्री कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को संचालित करेंगे।

- **पेशेवरों को तैयार करना**

नई शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में पेशेवरों को तैयार करने से जुड़ी शिक्षा के लिए यहां अनिवार्य है कि उसके पाठ्यक्रम में सार्वजनिक उद्देश्य एवं नैतिकता के महत्व का सम्मिलित हो और साथ ही साथ उसे विषय विशेष की शिक्षा और व्यवहारिक अभ्यास की शिक्षा

को भी समिलित किया जाए। अन्य समस्त उच्चतर शिक्षा से जुड़े विषयों की तरह ही इसके केंद्रों में भी तार्किक व अंतःविषय, सोच, चर्चा, नवाचार, अनुसंधान तथा विमर्श को समिलित किया जाना चाहिए।

- **कृषि शिक्षा और इससे संबंधित विषयों को पुनर्जीवित करना**

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है लगभग 85% लोग कृषि से संबंधित जीवन यापन करते हैं। व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत कृषि शिक्षा और उससे संबंधित विषयों को पुनर्जीवित करना अत्यंत आवश्यक है। विश्वविद्यालय में कृषि विश्वविद्यालय का प्रतिशत 9% है लेकिन कृषि और संबंधित विज्ञान विषयों में नामांकन उच्च उत्तर शिक्षा के कुल नामांकन की एक प्रतिशत से कम है। कुशल स्नातकों और तकनीशियनों, नवीन अनुसंधान तथा तकनीकी और कार्य प्रक्रियाओं से जुड़े बाजार आधारित विस्तार के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि और संबंधित विषयों की क्षमता और गुणवत्ता दोनों को बेहतर किया जाए।

- **नई शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा की मॉनीटरिंग करना**

नई शिक्षा नीति 2020 का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसकी मॉनीटरिंग करना आप सब जानते हैं। व्यवसायिक शिक्षा की सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में यह बात कही गई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अहम पहलू इसका मॉनीटरिंग है। व्यवसायिक शिक्षा की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर छात्रों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। जो छात्र पॉलिटेक्निक, आईटीआईटीआईटी और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित कौशल विकास कार्यक्रम में शामिल हुए उन सभी छात्रों की जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

- **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को प्रत्येक विषय व्यवसाय के लिए अधिक विस्तार पूर्वक निर्माण किया जाए**

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) को प्रत्येक विषय व्यवसाय तथा रोजगार के लिए अधिक से अधिक विस्तार पूर्वक निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ इस भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाए गए व्यापार तथा व्यवसाय के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ भी जोड़ा जाएगा। इस फ्रेमवर्क के पूर्ववर्ती शिक्षा की आवश्यकता के लिए आधार प्रदान करेगा। साथ ही साथ एनएसक्यूएफ ड्रॉप आउट हो चुके बच्चों के व्यवहारिक अनुभव को फ्रेमवर्क के प्रासंगिक स्तर के साथ जोड़ कर उन्हें पुनः औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

- **व्यवसायिक शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से सभी विद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्वीकृत किया जाएगा**

नई शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अकादमी शिक्षा के साथ-साथ व्यवसायिक शिक्षा का एकीकरण है। शैक्षणिक शिक्षा के साथ व्यवसायिक शिक्षा को एकीकृत करने के लिए अगले 10 वर्षों में चरणबद्ध योजनाओं के तहत माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों को व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पूर्व व्यवसायिक शिक्षा देने के साथ आरंभ होगी। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को आगे की व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी। साथ ही व्यवसायिक शिक्षा को छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के साथ भी सुचारू रूप से जारी रखने की योजना है। शैक्षणिक शिक्षा के साथ-साथ व्यवसायिक शिक्षा को एकत्रित करने के लिए कई अन्य योजनाएं भी इस नीति के अंतर्गत हैं।

- **व्यावसायिक शिक्षा के व्यवसायिक क्षेत्र का चुनाव स्थानीय अवसरों के आधार पर किया जाएगा**

व्यवसायिक शिक्षा के लिए व्यवसायिक क्षेत्र का चुनाव स्थानीय अवसरों के आधार पर किया जाएगा। हमारे देश में अलग-अलग तरीके से संस्कृतियों, रहन-सहन, खान-पान, भाषा तथा अन्य प्रकार की विभिन्नता होती है। इन्हीं विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में ऐसे पाठ्यक्रमों को समिलित किया जाएगा, जो स्थानीय अवसरों के हिसाब से बनाए जाएंगे। जहां पर जिस प्रकार की आवश्यकता होगी, बालकों को इस प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

- **व्यवसायिक शिक्षा के उन्नयन और विकास हेतु शिक्षा मंत्रालय उद्योगों के सहयोग से व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करेगा**

नई शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा को अधिक से अधिक उन्नयन तथा विकास करने हेतु भारत सरकार के तथा राज्य सरकार के उद्योग मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के साथ जोड़कर व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। अभी तक होता था कि शिक्षा मंत्रालय सिर्फ शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा

पर शिक्षा प्रदान करती थी वह सिर्फ अपने बालकों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही देती थी, उसे किताबी ज्ञान का उद्योगों तथा कारखाने में किसी प्रकार की सहायता नहीं प्राप्त होती थी।

- भारत के मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाए गए व्यवसाय के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ जोड़ा जाएगा

नई शिक्षा नीति में भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाए गए व्यापार तथा व्यवसाय के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ भी जोड़ा जाएगा। ताकि हमारे बालक जब व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर वह विदेशों में भी रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो कि आपने हमारी श्रमिक मानकों को पूरा नहीं किया है इसलिए अब हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी जो हमारे देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वैधानिक तरीके से मान्य हो।

- विद्यार्थियों को सामान्य से व्यवसायिक शिक्षा तक जाने को सरल बनाया जाएगा

नई शिक्षा नीति में शिक्षा मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय ने एक साथ एक कार्य योजना तैयार की है। जो व्यावसायिक शिक्षा को पुस्तकीय के ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करवाएगी। बालक जब यह व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए जाएगा, तो उसे पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ उक्त कार्य से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान भी होगा। जिससे उसे अपना कार्य करने में अधिक से अधिक सहायता प्राप्त होगी।

निष्कर्ष –

नई शिक्षा नीति के व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी शिक्षण एवं प्रशिक्षण छात्र-छात्राओं को प्रदान किए जाएंगे, इसका असर हमें भविष्य में एक मजबूत समाज व राष्ट्र के रूप में दिखाई देगा। साथ ही साथ छात्र-छात्राओं के अंदर बौद्धिक स्तर में बदलाव, मानसिक स्तर में बदलाव, सामाजिक स्तर पर बदलाव तथा राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव होगा। नई शिक्षा नीति के व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत हम एक ऐसे मजबूत व परिपूर्ण राष्ट्र का निर्माण होगा, जिसकी आधारशिला नई शिक्षा नीति 2020 की व्यवसायिक शिक्षा होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

- नए भारत की नींव राष्ट्रीय शिक्षा नीती 2020 – इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह
- शिक्षा नीति 2020 कुछ संस्तुतियाँ एवं विमर्श – डॉ सुधांशु कुमार पांडे
- नई शिक्षा नीति 2020 और मेरे विचार – जितेंद्र यादव
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रचनात्मक सुधारों की ओर – पंकज अरोड़ा एवं उषा शर्मा
- भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास एवं चुनौतियाँ – डॉ शालिनी त्यागी डॉ मनमोहन गुप्ता
- NEP_2020.pdf (ncert.nic.in)
- https://www.shikshaniti.com/2020/08/new-design-of-vocational-education.html?m=1#google_vignette
- <https://www.readermaster.com/new-national-education-policy/>
- <https://www.google.com/amp/s/www.franchiseindia.com/amp/hi/education/vocational-education-and-training.9416>
- <https://sstmaster.com/vocational-education-hindi/>
- <https://thehindipage.com/indian-education/bhartiya-shiksha-ka-itihaas-aur-vartamaan/>